

उत्तराखण्ड में बनेंगे ड्रोन कॉरडोर

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिये कॉरडोर बनाए जाएंगे। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने ड्रोन संचालन व निर्माण कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं।

प्रमुख बिंदु

- आईटीडीए की नदिशक नतिका खंडेलवाल ने बताया कि पिछले दिनों ड्रोन नीति बनाने के दौरान सभी हतिधारकों की बैठक हुई थी। इसमें हतिधारकों व विशेषकर ड्रोन निर्माता व संचालकों से संभावित ड्रोन कॉरडोर का प्रस्ताव मांगा गया है।
- उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव आने के बाद राज्य के हवाई नक्शे के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद राज्य में ड्रोन के कॉरडोर तय हो जाएंगे। सभी जिलों में ड्रोन संचालन के लिये जो कॉरडोर बनेंगे, उन्हें आपस में लकी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समर्पित रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नियम को तोड़ने वालों पर भविष्य में कार्रवाई भी हो सकेगी।
- ड्रोन कॉरडोर बनाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार किये जाएंगे, जो हवाई सेवाओं को बाधित न करें। वहीं, सीमांत प्रदेश होने के नाते तमाम प्रतिबंधित क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश में उत्तरकाशी से दून या अन्य जगहों पर ड्रोन संचालन का कोई समर्पित कॉरडोर नहीं है, जिससे कई ड्रोन को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे अधिक समय लगने और ड्रोन की बैटरी भी जल्द खत्म होने का खतरा है। ड्रोन कॉरडोर के बन जाने से उड़ान का समय तो कम होगा ही, उसकी बैटरी भी लंबी दूरी की उड़ान में मदद करेगी।
- ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के मद्देनजर उत्तराखण्ड सरकार जल्द ही ड्रोन नीति लाने जा रही है। आईटीडीए ने इसका ड्राफ्ट शासन को भेजा है। इसके तहत ड्रोन संचालन से लेकर ड्रोन की खरीद तक के सभी प्रावधान किये जाएंगे।



